रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256440
CG-DL-E-16082024-256440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3177] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946
No. 3177] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3493(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में दी जाने वाली सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 688(अ), तारीख 14 फरवरी, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को अंतिम रूप से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 फरवरी, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और उक्त उपखंड (vi) के परंतुक में यह उपबंध है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, इसे छह महीने से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि लोकहित में विस्तार की आवश्यकता

है, अधिसूचना संख्या का.आ. 688(अ), तारीख 14 फरवरी, 2024 में निर्दिष्ट अवधि को, 19 अगस्त, 2024 से छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त उद्योगों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होगी।

[फा. सं. एस-11017/04/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3493(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka, which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act declared the industrial undertakings under sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th February, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 688(E), dated the 14th February, 2024;

And whereas the proviso to said sub-clause (vi) provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period not exceeding six months;

Now,therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby, being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.688(E), dated the 14th February, 2024 for a further period of six months from the 19th August, 2024 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F.No. S-11017 / 04 / 2024- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.16 21:53:42 +05'30'